



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2006/6 पौष, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 27 दिसम्बर, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल०/1-60/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों

के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 26) जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

**हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन
विधेयक, 2006**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम,
1999 (2000 का 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित संक्षिप्त नाम।
का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2006 है ।

2. हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण धारा 6 का
अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (1) में, "सेशन न्यायालयों में से एक संशोधन ।
को विशेष न्यायालय के रूप में" शब्दों के स्थान पर "सभी या किन्हीं जिला
एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को नियन्त्रित करने और इन कम्पनियों में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का 19) अधिनियमित किया है। अधिनियम की धारा 6(1) यह उपबन्ध करती है कि सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, जिला और सेशन न्यायाधीश के वर्ग में एक विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "सेशन न्यायालयों में से एक को विशेष न्यायालय के रूप में" अभिहित कर सकेगी। तदनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति चाही गई थी। रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सूचित किया कि राज्य की स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत, न्याय के हित में यह समीचीन नहीं होगा कि केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला को ही सम्पूर्ण राज्य के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जाए, क्योंकि दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे कि चम्बा, किन्नौर और कांगड़ा से व्यथित व्यक्तियों को तब अपनी शिकायतों के निवारण के लिए शिमला आना पड़ेगा जो मुवक्किलों (लिटिगेन्ट पब्लिक) को असुविधा और कठिनाई पैदा करने के साथ-साथ घरद्वार पर न्याय देने के सिद्धान्तों के प्रतिकूल कदम होगा और साथ ही यह भी सुझाव दिया कि अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीशों के रूप में अभिहित किया जा सके। इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

तारीख..... 2006.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का 19) का
और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

डॉ० जे० एन० बारोवालिया,
सचिव (विधि) ।

शिमला:

तारीख....., 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS
(IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Amendment Act, 2006.

Amendment
of section 6.

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999, in sub-section (1), for the words "one of the Session Courts as a Special Court", the words "all or any of the District and Session Courts as Special Courts" shall be substituted.

19 of 2000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To control the activities of Non-Banking Financial Companies in the State and to protect the interests of depositors in these companies, the State Government has enacted the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000). Section 6(1) of the Act provides that the Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification, constitute a Special Court in the cadre of a District and Session Judge or designate one of the Session Courts as a Special Court for the purpose of this Act. Accordingly, the concurrence of the Chief Justice to designate the District and Session Judge, Shimla as Special Court was sought. The Registrar General, Himachal Pradesh High Court informed that in view of the topography and geographical condition of the State, it may not be expedient in the interest of Justice to designate only District and Session Judge, Shimla as Special Court for whole of the State as aggrieved persons from far-flung areas like Chamba, Kinnaur and Kangra will then have to come to Shimla for redressal of their grievances, which besides causing inconvenience and hardship to the litigant public will be a step contrary to the principles of imparting justice at the door steps and suggested that the Act is required to be suitably amended so as to designate all the District and Session Judges as Special Judges under this Act. Thus, it has been decided to amend section 6 of the Act *ibid* suitably. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The.....2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

**THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS
(IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2006**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

DR. J. N. BAROWALIA,
Secretary (Law).

SHIMLA:

The.....2006.